विचार वक्तव्य
जगदलपुर, गुरूवार 08 फरवरी 2018
www.dandakaranyasamachar.com

अमृत वाणी

सब प्राचीन अच्छा और सब नया बुरा नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष स्वतं परीक्षा द्वारा गुण दोशों का विवेचन करते हैं। -कालिदास,

देश में भ्रष्टाचार पर जब भी चर्चा होती है तो राजनीति को निशाना बनाया जाता है। आजादी के सत्तर साल बीत जाने के बाद भी भ्रष्टाचार को शक्तिशाली बनाने में राजनेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का होना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की राजनीति पर एक बदनुमा दाग है। इस दाग को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नारे को बुलन्द करते हुए सत्ता पर काबिज हुए अरविन्द केजरीवाल एवं उनकी सरकार हर दिन किसी नये घोटाले एवं भ्रष्टाचार के संगीन मामले को लेकर और गहरा कर रही हैं।

दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के दंश

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अनेक घोटाले एवं भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाये गये हैं और हर बार केजरीवाल उनकी रक्षा कर उन्हें सत्ता में कायम किये हुए हैं। जैन का एक और मामला सीबीआई की जांच के दौरान सामने आया है जिसने अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। मुख्य सवाल तो यहां सत्येन्द्र जैन जैसे राजनेताओं पर विश्वास करने का नहीं है, सवाल यहां ऐसे राजनेताओं की अपने कर्तव्य पराणता और पारदर्शिता का है। कब तक हम भ्रष्ट नेताओं को सहते रहेंगे और कब तक भ्रष्ट नेता देश के चरित्र को धुंधलाते रहेंगे।

सत्येन्द्र जैन के भ्रष्टाचार का मामला गंभीर एवं विडम्बनापूर्ण है। इस मामले में दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार और अधिवक्ता की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी और रजिस्ट्रार के लॉकर से सत्येंद्र जैन के नाम की संपत्ति के दस्तावेज बरामद होना आम आदमी पार्टी एवं अरविन्द केजरीवाल के कथनी और करनी की असामनता को बयां कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता इन दस्तावेजों को पुराना बता रहे हैं, लेकिन सीबीआइ द्वारा उनकी दलीलों को खारिज कर देने के बाद मंत्री के साथ ही आप सरकार भी कठघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। सीबीआइ ने दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार के लॉकर से जैन के नाम से तीन संपत्तियों के दस्तावेज, जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम की दो करोड़ रुपये की बैंक की डिपॉजिट स्लिप और 41 चेक बुक बरामद की हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सीबीआइ उनके विलाफकेस दर्ज कर जांच भी कर रही है। अब इन दस्तावेजों की बरामदगी पूर्व के आरोपों को कहीं-न-कहीं और पुख्ता करती है। यदि आम आदमी पार्टी की बात पर भरोसा कर भी लिया जाए तो भी एक सरकारी अधिकारी के लॉकर में मंत्री की निजी संपत्ति के दस्तावेज पाया जाना संदेह अवश्य पैदा करता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी दलों पर निशाना साधने के बजाय इन दलों के साथ ही दिल्ली की जनता को भी स्पष्ट करना चाहिए कि सच्चाई क्या है? जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफआवाज उठाकर सत्ता में आई है, उस पार्टी पर बार-बार भ्रष्टाचार के आरोप लगना गंभीर चिन्ता का विषय है। दिल्ली सरकार एवं आम आदमी पार्टी से इतनी नैतिकता की अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वह मंत्री पर लगे आरोपों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस मामले में सरकार को अपने स्तर पर कमेटी बनाकर भी जांच करनी चाहिए और यदि मंत्री दोषी पाए जाते हैं तो उनके विलाफसख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्री सत्येंद्र जैन पर इससे पूर्व हवाला कारोबार, जमीन कारोबार में धांधलियों, परिजनों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने, अस्पतालों में दवा एवं उपकरण खरीद धांधलियों सहित अनेक आरोप लगे हैं और अब उनके कागजात एक अधिकारी के लॉकर से बरामद होने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल सत्येंद्र जैन की आर्थिक धांधलियों को संरक्षण दे रहे हैं, उसे देखकर केजरीवाल पर भी संदेह होना स्वाभाविक हैं। ताजा प्रकरण के बाद कहीं-न-कहीं ऐसा लगता है कि मंत्री सतेन्द्र जैन एवं रजिस्ट्रार अधिराज के बीच कोई न कोई आर्थिक रिश्ते हैं जिनकी जांच आवश्यक है और कोई भी जांच तब तक पारदर्शी नहीं से सकती जबकि सतेन्द्र जैन अपने पद पद बने हुये हैं। लगातार भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर दिल्ली सरकार द्वारा पर्दे डालने का दुष्प्रभाव और सीधा-सीधा असर सरकार के कार्यों पर दिख रहा है, इन बढ़ती भष्ट और अराजक स्थितियों को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। अन्यथा दिल्ली की सारी प्रगति को भ्रष्टाचार की महमारी खा जाएगी।

दिल्ली सरकार शर्म्शार-तानाशाही की मुद्रा में है, वह कुछ भी कर सकती है, उसको किसी से भय नहीं है, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता- इसी सोच ने उसे भष्टचारी बनाया है। जहां नियमों की पालना व आम जनता को सुविधा देने के नाम पर भोली-भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, ठगा जा रहा हैं। आप की चादर इतनी मैली है कि लोगों ने उसका रंग ही काला मान लिया है। अगर कहीं कोई एक प्रतिशत ईमानदारी दिखती है तो आश्चर्य होता है कि ह्त कौन है? पर ह्त्दी की एक गांठ लेकर थोक व्यापार नहीं किया जा सकता है। आप राजनेताओं की सोच बन गई है कि सत्ता का वास्तविक लक्ष्य सेवा नहीं, धन उगाई है।

राजनेता से मंत्री बने व्यक्ति अंततः लोकसेवक हैं। उन पर गुरु दायित्व को निर्मित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं या किसी गंभीर लापरवाही को अंजाम देते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होनी ही चाहिए और इसका अहसास भी उन्हें रहना चाहिए। राजनेताओं विशेषतः दिल्ली सरकार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार इस लिहाज से भी एक बड़ा अपराध है कि इस कारण से इसकी जड़ें प्रशासन के निचले स्तर तक जाती हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक सिरा राजनीतिक भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है। यही कारण है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्ट मंत्रियों का संरक्षण भी प्राप्त होता है और इसी का उदाहरण है दिल्ली डेंटल कांउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. अर्षि राज की गिरफ्तारी एवं उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगना।

दिल्ली देश की धड़कन है, उसकी शासन-व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सक्षम और ईमानदार राजनेताओं का होना जरूरी है, यह बात केजरीवालजी एवं उनकी सरकार के मंत्रियों को समझनी होगी। अन्यथा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा तथा दिल्ली के सर्वांगीण विकास की राह बाधित रहेगी। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार तो भारत की आत्मा में रच-बस गया है। इसे सख्त कानून से नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र को सुदृढ़ बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है। जहां तक अपराधियों के कालेधन का सवाल है तो सरकार उनके प्रति उतना बलपूर्वक कदम नहीं उठाती है क्योंकि कहीं-न-कहीं सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई देती है। ईमानदारी और नैतिकता शतरंज की चालें नहीं, मानवीय मूल्य हैं। इस बात को समझकर ही हम राजनीति एवं सरकारों में पारदर्शिता, जबाबदेही एवं ईमानदारी को स्थापित कर सकेंगे। भ्रष्टाचार शासन एवं प्रशासन की जड़ों में इतना गहरा पैठा हुआ है कि इन विकट एवं विकराल स्थितियों में एक ही पंक्ति का स्मरण बार बार होता है, घर-घर में है रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। भ्रष्टाचार, बेईमानी और अपप्रशाशी इतना हावी हो गया है कि लोकतंत्र में सांस लेना भी दूभर से गया है। आखिर हम कब नींद से जागेंगे। कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है। हमारे देश की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक हैं यह अच्छी बात है लेकिन इन चर्चाओं के बीच हमारे देश का भ्रष्टाचार भी दुनिया में चर्चित है, इसे तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें जरूरत है इसको रोकने की। हमें यह कहते हुए शर्म भी आती है और अफ्सोस भी होता है कि हमारे पास ईमानदारी नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं हैं। राष्ट्र में जब राष्ट्रीय मूल्य कमजोर से जाते हैं और सिर्फ निजी स्वार्थ और निजी हैसियत को ऊंचा करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह राष्ट्र निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है और ह्तदर्सों का राष्ट्र बन जाता है।

ललित गर्ग
(दे लेखक के अपने विचार हैं)

बढ़ते ही जा रहे ठगी के कारोबार

इन दिनों ठगी का धंधा मानो एकाएक जोर शोर से चलने लगा है। एक ओर जगह जगह सरकारें चिटफंड कंपनी को लेकर परेशानी में हैं वहीं दूसरी ओर कभी कोई बिल्डर तो कभी कोई कंपनी और कभी कोई व्यक्ति किसी को भी अपनी ठगी का शिकार बनाने में लगा हुआ है। कोई जमा रकम दुगुना करने का सपना दिखाकर किसी की गाढ़ी कमाई हड़प रहा है तो कोई रोजगार दिलाने के नाम पर, कोई मकान या जमीन दिलाने के नाम पर किसी के जीवन भर के संचय पर हाथ मार रहा है, कोई गहने के नाम पर ठगी कर रहा है और कोई विदेश यात्रा के नाम पर। अर्थात ठगी के उपाय और आधार का अंत नहीं है। बस ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसे गिरफ्त में लेना आसान हो। लोग भी मानो वशीभूत की तरह उनकी ओर खींचे चले जाते है, बेसुध से होकर और अंततः जब उन्हें होश आता है और अपनी गलती का एहसास होता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि उनके लिए माथा पीटने के अलावा और कोई राह शेष नहीं बचता। पुलिस तक शिकायत भी चूंकि मामला पूरी तरह बिगड़ने के बाद पहुंचती है इसलिए उसके लिए भी आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम आरोपी इतने शातिर होते है कि वे अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ते। इसलिए पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाता है।

हाल में प्रकाश में आए एक वरिष्ठ नागरिक की बिल्डर के ठगी का शिकार होने की घटना पर गौर करें। आशियाना उपलब्ध कराने के नाम पर एक बिल्डर ने उनसे उनके जीवन भर का संचय हड़प लिया। सर्वसुविधायुक्त 4 बीएचके मकान का सपना संजोकर अपने जीवन भर के मेहनत की कमाई सौंपने वाले ये पीड़ित आज एक छोटे से किराए के घर में रहकर अपने किस्मत को कोसने को मजबूर है। वो कितने हताश और त्रस्त है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कहते हैं रूपये मिले न मिले उस बिल्डर को सजा करवा दो। बताया जाता है कि इस बिल्डर ने ऐसे कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।

ऐसे ही एक दूसरे ठगी के मामले में ग्रापं मावलीपदर में एक कंपनी ने दोगुना ब्याज का लालच देकर ग्रामीणों से मजदूरी कर कमाए गए पैसों को जमा करवाया गया। एक-एक ग्रामीण ने 10 से 50 हजार तक की राशि इस कंपनी के पास जमा कराया। कंपनी के एजेंट ने घर घर जाकर यह रकम जमा कराई। अब जब ग्रामीण पैसा वापसी के बारे में पूछते हैं तो हमें नहीं मालूम कहकर अभद्र व्यवहार किया जाता है। निराश ग्रामीण अंततः पुलिस का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुए हैं।

ऐसे कई मामले है जिनमें लोगों को ठगी का शिकार किया जाता है। नौकरी दिलाने के नाम पर तो लोगों को बड़ी आसानी से जाल में फंसा लिया जाता है। इसमें पीड़ितों की गलती भी कम नहीं होती। वे बिना समझे बुझे किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले उनका सतर्क होना जरूरी है तभी इस धंधे पर अंकुश संभव है।

राजकाज

केजरीवाल बनाम एलजी, सीबीआई, ईसी और सीजी

जब से अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में सत्तासीन हुए हैं तभी से उन्हें कमजोर करने की कोशिशें राजनीतिक स्तर पर खूब हुईं लेकिन इसमें सफल नहीं होने के बाद अब उनका मुकाबला एलजी, ईसी, सीबीआई और सीजी से हो गया है। यह आरोप आम आदमी पार्टी के नेता समय-समय पर लगाते रहे हैं, लेकिन एक महीने के भीतर केजरीवाल को दूसरा झटका देते हुए सीबीआई ने जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा है उससे भी कहानी पुख्ता होती नजर आ रही है। दरअसल पहले आरोप लगाकर मंत्रियों को बाहर करने का खेल खेला गया। फिर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच फैसलों को लेकर विवाद हुए। केंद्र सरकार ने भी दिल से मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपमानित महसूस कराया, चुनाव आयोग से भी आप का नाता विवादों वाला ही रहा और इन सब से परे सीबीआई अब आप को खासतौर पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों को सबक सिखाने की भूमिका में नजर आ रही है।

मन की बात नहीं दिल की बात सुनें

मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ही तंज कसते नजर आ रहे हैं। दरअसल नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर किसानों ने धरना आंदोलन किया। जिसमें भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा भी शामिल हुए। इतना ही नहीं फिल्म अभिनेता व सांसद शत्रुघ्न ने किसानों को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि वो मन की बात नहीं करते बल्कि वो तो दिल से बात करते हैं। सुनने वाले समझ ही गए कि यह तंज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हैए क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार मन की बात करते चले जा रहे हैं और गरीब पीड़ित किसान आत्महत्या को प्रेरित हो रहे हैं। बहरहाल इन नेताओं ने राष्ट्र मंच को सक्का मंच निरुपित करते हुए कह दिया कि आंदोलन में हम किसानों के साथ हैं। यह अलग बात है कि उसके बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई।

रोकना ही होगा टीबी की बीमारी को?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के पोषण के लिए सरकार ने सहायता स्वरूप 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि देश में जिन टीबी रोगियों का इलाज चल रहा है उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सरकार ने इस भयंकर बीमारी को 2025 तक जड़ से खत्म करने की घोषणा कर दी है। सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को सहायता मुहैया कराने की पहल राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का हिस्सा है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

गौरतलब है कि दुनियाभर में बीमारियों से मौत के 10 शीर्ष कारणों में तपेदिक को प्रमुख बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में दुनिया भर के 24 फीसदी टीबी के मामले हैं और इससे हर साल पांच लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। यानी देश में हर तीन मिनट में दो भारतीयों की मौत हो जाती है। 2016 में जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 28 लाख टीबी के नये मरीज पंजीकृत होते हैं। टीबी भारत की सबसे बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीबी उन्मूलन अभियान को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर लिया है। विश्व में भारत पर टीबी का बोझ सबसे अधिक है। देश ने टीबी उन्मूलन को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। इसका उद्देश्य टीबी के नए मामलों में 95 प्रतिशत की कमी करना और टीबी से मृत्यु में 95 प्रतिशत की कमी लाना है।

भारत में साल 2015 में टीबी (तपेदिक) से मरनेवालों की संख्या 4,80,000 थी, जो साल 2014 में इस रोग से हुई 2,20,000 मौतों से दोगुनी थी। इसका कारण है कि पहले की मौतों के जो अनुमान लगाए गए थे वे गलत थे। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी की 2016 में जारी रिपोर्ट से सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 27 फीसदी टीबी के मामले भारत में हैं। देश में यह सबसे घातक संक्रामक रोग है। साल 2015 में देश में 28 लाख टीबी के नए मामले सामने आए, जबकि 2014 में नए मामलों की संख्या 22 लाख थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे %यादा टीबी के मामले भारत में पाए जाते हैं।

भारत में टीबी की दवा के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता रखनेवाले मरीजों की संख्या 2015 में 79,000 थी, जो 2014 के मुकाबले 11 फीसदी अधिक है। नए टीबी के मामलों में करीब 2.5 फीसदी मामले ऐसे आ रहे हैं, जिन्होंने टीबी की दवा के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है और उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में टीबी अनुमान की तुलना में कहीं अधिक बड़ी महामारी है। यह निगरानी और सर्वेक्षण के नए आंकड़ों से पता चला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत टीबी से निपटने को लेकर गंभीर नहीं है। अपनी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2016 में उसने हमारे आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है। उसके मुताबिक भारत ने वर्ष 2000 से 2015 के बीच टीबी के जितने मामले बताए हैं, वास्तव में मरीज उससे कहीं %यादा रहे हैं। भारत के गलत आंकड़ों की वजह से इस रोग का विश्वस्तरीय आकलन ढंग से नहीं हो पाया। भारत ने 2014 में कुल मामलों का 56 प्रतिशत और 2015 में 59 प्रतिशत ही दर्ज कराया। असल में ये वे आंकड़े हैं जो सरकारी अस्पतालों में दर्ज किए जाते हैं। इनमें निजी स्वास्थ्य केन्द्रों से मिले आंकड़े नाममात्र को ही होते हैं, जिसकी वजह से टीबी के मरीजों की असली संख्या का पता नहीं चल पाता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खुद स्वीकार करता है कि देश में टीबी के साठ प्रतिशत मरीज निजी अस्पतालों या डॉक्टरों से अपना इलाज कराते हैं जिनमें से महज 15 प्रतिशत की ही रिपोर्ट सरकार तक पहुंच पाती है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2016 के मुताबिक टीबी की महामारी उससे कहीं %यादा बड़ी हो चुकी है जितनी दिखती है। दुनिया के छह देशों- भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में इसके साठ प्रतिशत नए मरीज दर्ज किए गए हैं। टीबी रोग से ग्रसित दस फीसद मरीज दवाइयां बीच में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बीमारी दोबारा जकड़ लेती है।

भारत में सन 1956 में पहली बार टीबी का सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद अब परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग टीबी का दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने जा रहा है। इसके बाद भी देश में टीबी के सभी मरीजों का पता चल ही जाएगा यह कहना मुश्किल है। पिछले कुछ समय से टीबी के कई नए रूप सामने आ गए हैं। कई मानसिक बीमारियां टीबी का बड़ा कारण बनकर उभरी हैं। इस बीमारी को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। सरकार परम्परागत तौर-तरीके से बाहर निकले। इससे निपटने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर व्यापक योजना बनानी होगी। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। शहरों में तो निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों की वजह से तस्वीर कुछ उजली नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि इन महंगी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाने में कितने लोग सक्षम हैं? छोटे कस्बों व गांवों में तो सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के शिकार हैं। वहां न तो डॉ० के अस्पताल हैं और न ही दवाएं।

विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को इस क्षेत्र में एक ठोस अभियान शुरू करना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस जानलेवा बीमारी पर काबू पाने की राह में पैसों की कमी आड़े नहीं आए। ऐसा नहीं हुआ तो इससे मरने वालों की तादाद लगातार तेजी से बढ़ेगी। लेकिन क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से उसकी कुंभकर्णी नींद टूटेगी? इन और ऐसे कई अन्य सवालों के जवाब ही देश और दुनिया में टीबी पर अंकुश लगाने की लड़ाई की दशा-दिशा तय करेंगे।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टीबी को मिटा फेंकने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे हाथों हाथ लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस भयंकर रूप में यह बिमारी हमारे देश में फैली है क्या उसे देखना लाजिमी नहीं होगा? क्या यह संभव हो पाएगा कि टीबी सचमुच आने वाले नौ-दस सालों में जड़ से खत्म हो जाए। यदि हां तो इसको जड़ से खत्म करने का रोडमैप क्या होगा? अभी तो इसकी गंभीरता को देखते हुए यह लगता है कि यह बिमारी कम होने की बजाय और अधिक तेजी से बढ़ रही है।

रमेश सर्राफ धमोरा
(दे लेखक के अपने विचार है)

वेलेंटाइन डे की शुरुआत

छाया हुआ मधुमास है। खिला हुआ अमलतास है। बागों में बहार है। कलियों पर निखार है। जिया झूमने को तैयार है। आया वेलेंटाइन डे का त्योहार है। जी ! हांए आपने सही सुना। वेलेंटाइन डे यानि प्रेम दिवस दस्तक दे रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सात से चौदह फरवरी तक प्रेमी प्रेम की समस्त सीमाएं तोड़कर प्रेमिका को यह जताने में लगा मिलेगा कि उससे बड़ा दिलफेंक आशिक इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेमी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए तरह.तरह के जतन करता हुआ नज़र आएगा। मसलन चॉकलेट देगाए टेडी बियर देगाए गुलाब का फूल भेंट करेगाए बाप के पैसों से गर्लफ्रेंड को सिनेमा दिखायेगा। सिनेमा दिखाते.दिखाते पॉपकॉर्न भी खिलाएगा। ये कहे कि प्यार में आशिक़ कुत्ता तक बन जायेगा। और प्रेमिका को खुश करने के लिए घरवालों को रोड पर लायेगा। संत वेलेंटाइन की यह संतान सात जन्मों वाले प्रेम को एक दिन का बनाकर ही दम लेगी। इसी का फ़ायदा उठाकर विदेशी कंपनियां भी माल कमा लेगी। क्योंकि विदेशियों ने अभी तक भारतीयों को मूर्ख बनाना बंद नहीं किया हैं। और भारतीयों ने भी मूर्ख बनना बंद नहीं किया हैं। खेल को दोनों देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन घाटा एक देश झेल रहा है। वो देश हमारा ही है। जिस देश में प्रेम के सबसे बड़े पुरोधा कृष्ण अवतरित हुए। लैला.मजनू ने इस परम्परा को आगे बढ़ायाए शाहजहां मुमताज ने भी प्रेम का सच्चा मर्म बताया। वहां संत वेलेंटाइन के नाम पर केवल एक दिन को प्रेम दिवस मनाना उचित नहीं लगता है। प्रेम की उम्र एक दिन तो कतई नहीं हो सकती है। प्रेम जैसे शाश्वत सर्जन को एक दिन का करार देने वाला सच्चा प्रेमी नहींए वो तो केवल चमड़ी का पुजारी ही हो सकता है। जिसके लिए प्रेम का दृष्टिकोण इंच.इंच और सेंटीमीटर.सेंटीमीटर का होता है। जिसके लिए रूह नहीं जिस्म ही सर्वस्व है। ऐसे वेलेंटाइन डे वाले प्रेमियों के लिए प्यारए सेक्स और धोखे के आगे दुनिया में कुछ भी महत्व नहीं रखता हैं। यकीकन ! प्रेम के मयाने बदल चुके हैं। इसलिए आजकल के प्रेमियों को प्रेमिका की नज़रों में महान घोषित होने के लिए खुद की जान.वान देनी की जरूरत नहीं पडती है। आज तो बस मंहगी.महंगी गिफ्ट देकर और अच्छी.सी शॉपिंग कराकर ही काम बन जाता है। यह कहे कि आपके प्रेम में कितना दम है यह आपकी जेब में रखे विटामिन एम से ही पता चलेगा। जो प्रेमी जितना खर्चा अपनी प्रेमिका के नाम पर करेगा वो उतना ही बड़ा प्रेमी कहलायेगा। प्रेम का पैमाना पैसा है। हक़ीकत तो यह है कि जिस्म को देखकर प्रेम करने की परिपाटी भी चली गई हैए अब तो प्रेमिका का प्रेम केवल और केवल पैसा देखता है। और ऐसे ही पैसों का प्रदर्शन करने का दिन वेलेंटाइन डे है।

देवेंद्रराज सुथार
(दे लेखक के अपने विचार है)